



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 746]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 26, 2019/ पौष 5, 1941

No. 746]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 26, 2019/ PAUSHA 5, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2019

सं. 74/2019-केन्द्रीय कर

**सा.का.नि. 953(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 53(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्यांक 4/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 23 जनवरी, 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस की रकम ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो मास/तिमाही जुलाई, 2017 से नवंबर, 2019 तक के लिए, देय तारीख तक **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे देने में असफल रहे हैं, किंतु उन्होंने 19 दिसंबर, 2019 से 10 जनवरी, 2020 तक की बीच की अवधि के उक्त ब्यौरे **प्ररूप जीएसटीआर-1** में दे दिए हैं।”।

2. यह अधिसूचना 19 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. 20/06/09/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना संख्यांक 4/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 23 जनवरी, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 53(अ), तारीख 23 जनवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 75/2018-केन्द्रीय कर, तारीख 31 दिसंबर, 2018, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 1252(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2018 द्वारा संशोधित की गई थी।

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th December, 2019

**No. 74/2019–Central Tax**

**G.S.R. 953(E).**—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 4/2018– Central Tax, dated the 23rd January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i) vide number G.S.R. 53(E), dated the 23rd January, 2018, namely:—

In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for the months/quarters from July, 2017 to November, 2019 by the due date but furnishes the said details in **FORM GSTR-1** between the period from 19th December, 2019 to 10th January, 2020.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 19th day of December, 2019.

[F. No. 20/06/09/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 4/2018-Central Tax, dated 23rd January, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 53(E), dated the 23rd January, 2018 and was subsequently amended by notification No. 75/2018-Central Tax, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 1252(E), dated the 31st December, 2018.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2019

**सं. 75/2019-केन्द्रीय कर**

**सा.का.नि.954(अ).**—केन्द्रीय सरकार, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2019 है।  
(2) जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 36 के उपनियम (4) में, 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी, “20 प्रतिशत” अंक और शब्द के स्थान पर “10 प्रतिशत” अंक और शब्द रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों के नियम 86 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**“86क. इलेक्ट्रानिक जमा खाते में उपलब्ध रकम के उपयोग की शर्तें.-**

- (1) आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, जो सहायक आयुक्त की श्रेणी से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इलेक्ट्रानिक जमा खाते में उपलब्ध इनपुट कर के प्रत्यय का कपटपूर्वक उपभोग किया गया है या वह अपात्र है, उस सीमा तक जिस तक वह -

क) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग,-

(i) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जिसे अस्तित्वहीन पाया गया है या जो ऐसे किसी स्थान से, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्रास किया गया है, कोई कारबार नहीं चला रहा है, द्वारा जारी ; या

(ii) माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति के बिना,

कर बीजकों या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर किया गया है ; या

ख) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग, किसी ऐसे प्रदाय के संबंध में जिसकी बाबत प्रभारित कर सरकार को संदत्त नहीं किया गया है ; कर बीजकों या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर किया गया है ; या

ग) इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अस्तित्वहीन पाया जाता है या ऐसे किसी स्थान से, जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण अभिप्रास किया गया है, कोई कारबार नहीं चला रहा है ; या

घ) इनपुट कर के किसी प्रत्यय का उपभोग करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के कब्जे में कर बीजक या नामे नोट या नियम 36 के अधीन विहित कोई अन्य दस्तावेज नहीं है,

लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, धारा 49 के अधीन किसी दायित्व के निर्वहन के लिए या किसी अनुपयोजित रकम के किसी प्रतिदाय के दावे के लिए इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में से ऐसे प्रत्यय के समतुल्य किसी रकम का विकलन अनुज्ञात नहीं कर सकेगा ।

(2) आयुक्त या उपनियम (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यह समाधान हो जाने पर कि इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते के विकलन को अनुज्ञात करने की यथा उपरोक्त शर्तें अस्तित्व में नहीं हैं, ऐसे विकलन को अनुज्ञात कर सकेगा ।

(3) ऐसे निबन्धन, उस तारीख से, जिसको ऐसे निबन्धन अधिरोपित किए जाएं, एक वर्ष की अवधि की समाप्त के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेंगे ।

4. उक्त नियमों में, 11 जनवरी, 2020 से प्रभावी, नियम 138ड में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति ने, यथास्थिति, दो मास के लिए या दो तिमाही के लिए जावक प्रदायों का विवरण नहीं दिया है ।”।

[फा. सं. 20/06/09/2019-जीएसटी]

रुचि विष्ट, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा सा.का.नि. 924(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 68/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 13 दिसंबर, 2019 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था ।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2019

### No. 75/2019—Central Tax

**G.S.R. 954(E).**—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2019.
- (2) Save as otherwise provided, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), with effect from the 1st January, 2020, in rule 36, in sub-rule (4), for the figures and words “20 per cent.”, the figures and words “10 per cent.” shall be substituted.
- In the said rules, after rule 86, the following rule shall be inserted, namely:-

“86A. Conditions of use of amount available in electronic credit ledger.-

- (1) The Commissioner or an officer authorised by him in this behalf, not below the rank of an Assistant Commissioner, having reasons to believe that credit of input tax available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible in as much as-
- a) the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36-
    - i. issued by a registered person who has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained; or
    - ii. without receipt of goods or services or both; or
  - b) the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoices or debit notes or any other document prescribed under rule 36 in respect of any supply, the tax charged in respect of which has not been paid to the Government; or
  - c) the registered person availing the credit of input tax has been found non-existent or not to be conducting any business from any place for which registration has been obtained; or
  - d) the registered person availing any credit of input tax is not in possession of a tax invoice or debit note or any other document prescribed under rule 36,

may, for reasons to be recorded in writing, not allow debit of an amount equivalent to such credit in electronic credit ledger for discharge of any liability under section 49 or for claim of any refund of any unutilised amount.

(2) The Commissioner, or the officer authorised by him under sub-rule (1) may, upon being satisfied that conditions for disallowing debit of electronic credit ledger as above, no longer exist, allow such debit.

(3) Such restriction shall cease to have effect after the expiry of a period of one year from the date of imposing such restriction.”.

4. In the said rules, with effect from the 11th January, 2020, in rule 138E, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) being a person other than a person specified in clause (a), has not furnished the statement of outward supplies for any two months or quarters, as the case may be.”.

[F. No. 20/06/09/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published *vide* number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and last amended *vide* notification No. 68/2019-Central Tax, dated the 13th December, 2019, published *vide* number G.S.R. 924(E), dated the 13th December, 2019.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2019

### सं. 76/2019-केन्द्रीय कर

**सा.का.नि. 955(अ).—**आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (1) की दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 46/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 9 अक्टूबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 769(अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पहले पैरा के परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनका मूल कारबार स्थान असम, मणिपुर या त्रिपुरा राज्य में है, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग की दशा में, जिनका समय आवर्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष या चालू वित्त वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक है, नवंबर, 2019 मास के लिये, समय-सीमा, 31 दिसंबर, 2019 तक है।”

2. यह अधिसूचना 11 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. 20/06/09/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवसर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना सं. 46/2019-केंद्रीय कर, तारीख 09 अक्टूबर, 2019 भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 769(अ), तारीख 09 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी। और पश्चातवर्ति संशोधन संख्या 64/2019-केंद्रीय कर, तारीख 12 दिसंबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 908(अ) तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2019

### No. 76/2019–Central Tax

**G.S.R. 955(E).**—In exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 46/2019–Central Tax, dated the 9th October, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 769(E), dated the 09th October, 2019, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that for registered persons whose principal place of business is in the State of Assam, Manipur or Tripura, the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of Central Goods and Services Tax Rules, 2017, by such class of registered persons having aggregate turnover of more than 1.5 crore rupees in the preceding financial year or current financial year, for the month of November, 2019 till 31st December, 2019.”

2. This notification shall be deemed to come into force with effect from the 11th Day of December, 2019.

[F. No. 20/06/09/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 46/2019–Central Tax, dated the 09th October, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 769(E), dated the 09th October, 2019 and was last amended by notification No. 64/2019–Central Tax, dated the 12th December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 908(E), dated the 12th December, 2019.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2019

### सं. 77/2019-केन्द्रीय कर

**सा.का.नि. 956(अ).**—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 44/2019-केंद्रीय कर, तारीख 9 अक्टूबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 767(अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की दशा में, जिनका मूल कारबार स्थान असम, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा राज्य में है, नवंबर 2019 मास के लिए, उक्त नियमों के **प्रारूप जीएसटीआर-3ब** में विवरणी इलेक्ट्रॉनिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 31 दिसंबर, 2019 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।”।

2. यह अधिसूचना 23 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. 20/06/09/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना सं. 44/2019-केंद्रीय कर, तारीख 9 अक्टूबर, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 767(अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 73/2019-केंद्रीय कर, तारीख 23 दिसंबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 943(अ) तारीख 23 दिसंबर, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2019

#### No. 77/2019 – Central Tax

**G.S.R.956(E).**—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 44/2019 – Central Tax, dated the 09th October, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.767(E), dated the 09th October, 2019, namely:—

In the first paragraph of the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the month of November, 2019 for registered persons whose principal place of business is in the State of Assam, Manipur, Meghalaya or Tripura, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 31st December, 2019.”

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 23rd day of December, 2019.

[F. No. 20/06/09/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 44/2019–Central Tax, dated the 09th October, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.767(E), dated the 09th October, 2019 and was last amended by notification No. 73/2019–Central Tax, dated the 23rd December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 943(E), dated the 23rd December, 2019.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2019

#### सं. 78/2019-केंद्रीय कर

**सा.का.नि. 957(अ).**—आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, तीसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु यह और भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों की दशा में, जिनका मूल कारबार स्थान असम, मणिपुर या त्रिपुरा राज्य में है, जिनसे उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अधीन केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर-7** में स्रोत पर कर कटौती की अपेक्षा है, नवंबर, 2019 के लिए विवरणी इलैक्ट्रानिकी रूप से सामान्य पोर्टल के माध्यम से 25 दिसंबर, 2019 को या उससे पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।”।

2. यह अधिसूचना 10 दिसंबर, 2019 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

[फा. सं. 20/06/09/2019-जीएसटी]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना सं. 26/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 65/2019-केंद्रीय कर, तारीख 12 दिसंबर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 909(अ) तारीख 12 दिसंबर, 2019 द्वारा संशोधित की गई थी।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2019

#### No. 78/2019—Central Tax

**G.S.R. 957(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Commissioner hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 26/2019—Central Tax, dated the 28th June, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 452(E), dated the 28th June, 2019, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that the return by a registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act in **FORM GSTR-7** of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 under sub-section (3) of section 39 of the said Act read with rule 66 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of November, 2019, whose principal place of business is in the State of Assam, Manipur or Tripura, shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 25th December, 2019.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 10th Day of December, 2019.

[F. No. 20/06/09/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 26/2019—Central Tax, dated the 28th June, 2019 was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 452(E), dated the 28th June, 2019 and was last amended by notification No. 65/2019—Central Tax, dated the 12th December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 909(E), dated the 12th December, 2019.